राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष ३३ अंक १ अप्रैल २०११ नयी दिल्ली मूल्य ५ रु. पृष्ठ ३२

भ्रष्टाचार के खिलाफ अभाविप मुखर

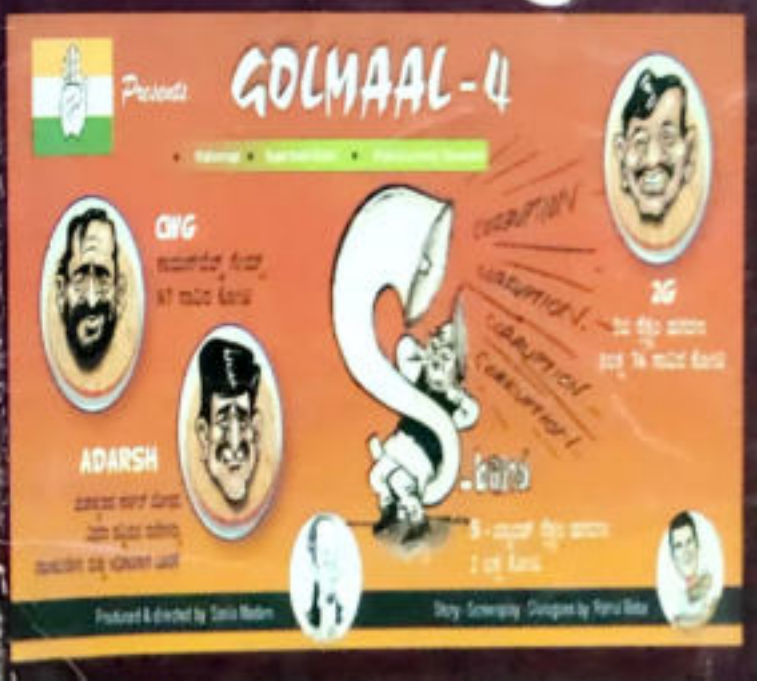

संविधान निर्माण की मांग को लेकर आन्दोलनरत प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल के कार्यकर्ता

दिल्ली में राधिका तंवर के हत्यारों की गिरफतारी की मांग करते आकोशित छात्र

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक:
आशुतोष

सम्पादक मण्डल:
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह

फोन : 011-43098248
ईमेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाइट : www.abvp.org

मुद्रक और प्रकाशक राजकुमार शर्मा द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, बी-५०, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल इंस्टीट्यूट, दिल्ली-११०००७ के लिए प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के.३० नवीन शहादरा, दिल्ली- ३२ द्वारा मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय :
"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005.

अनुक्रमणिका

विषय	लेखक	पृ.सं.
संपादकीय		४
उदार नीतियां, बदहाल शिक्षा	संजय द्विवेदी	६
छात्राओं के शोषण में शिक्षकों की संलिप्तता दुर्भाग्यपूर्ण : विष्णुदत्त शर्मा		८
तकनीकों पर भारी कुदरत का कहर	स्वाती जैन	९
भोपाल में 'छात्रशक्ति' कार्यालय का लोकार्पण		१२
युवा और राजनीति	विजय कुमार	१६
संप्रग सरकार के घोटालों का रिपोर्टकार्ड	अवनीश सिंह	१९
भ्रष्टाचार कैंसर की तरह लाइलाज नहीं	एन. आर. नारायणमूर्ति	२१
ऐसे मिटाएँ भ्रष्टाचार	डॉ. वेदप्रताप वैदिक	२४
भ्रष्टाचरण और कांग्रेस	सुरेन्द्र चतुर्वेदी	२८

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

जीत का अपना खुमार होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के विश्वचषक विजेता बनने के खुमार में पूरा देश झूम रहा है। २८ वर्षों बाद भारतीय टीम ने देश को यह सम्मान दिलाया है। देश ने भी भारतीय टीम को उसकी इस उपलब्धि के लिये सर-आंखों पर बिठाया है जो स्वाभाविक ही है।

फरवरी माह से ही क्रिकेट का रंग छाने लगा था जो फाइनल तक पहुंचते-पहुंचते दीवानगी में बदल गया। भारतीय टीम ने भी श्रेष्ठ प्रदर्शन से दर्शकों की उम्मीद को बनाये रखा। पाकिस्तान से हुआ सेमीफाइनल और श्रीलंका के साथ खेले फाइनल में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। खेल के अंत तक रोमांच बरकरार रहा। हारने वाली दोनों टीमों ने भी इस रोमांच को बनाये रखने में पूरा साथ दिया।

१९७५ से प्रारंभ हुए विश्वचषक ने दुनियां भर में क्रिकेट के प्रति रुचि जगायी है। पहले तीन टूर्नामेंट तक ६० ओवरों में खेले जाने वाला एक दिवसीय बाद में ५० ओवरों तक सीमित कर दिया गया। इस समय तक भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल औपचारिक उपस्थिति रहती थी। पहले विश्वचषक में अपने समय के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पूरे साठ ओवर की पारी खेली और कुल ३६ रन बनाये। लेकिन इन अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों ने तत्कालीन भारतीय टीम को मांजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

लंदन में लॉर्डस के मैदान पर खेले गये तीसरे विश्वचषक के मुकाबले में पहले दोनों टूर्नामेंट की विजेता रही अपराजेय मानी जाने वाली वेस्ट इंडीज को जब कपिलदेव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पराजित किया तो यह किसी भी भारतीय के लिये आश्चर्यजनक तो दुनियां की क्रिकेट महाशक्तियों के लिये किसी सदमे से कम न था।

कपिलदेव और सुनील गावसकर के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अनेक सफलतायें बटोरीं। भारतीय टीम और खिलाडियों ने इस बीच अनेक कीर्तिमान बनाये। पीढ़ियां बदलीं। लेकिन अगला विश्वचषक उसके हाथ से दूर ही रहा।

१९८३ के बाद से ही हर आयोजन में देश ने अपनी टीम से उम्मीदें बनाये रखीए हालांकि वे पूरी न हो सकीं। २००७ में हुए पिछले विश्वचषक में तो बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर भारत पहले ही चक्र में बाहर हो गया। इस बीच भारतीय खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगे। २०.२० के फटाफट क्रिकेट का भी दौर आया। खिलाडियों की नीलामी का भी अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला।

२०११ में विश्वचषक के आतिथ्य का अवसर भारत को मिला। कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के नेतृत्व में बुलंद हौंसले के साथ भारतीय टीम ने मजबूत प्रदर्शन किया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने टीम भावना का बेहतर प्रदर्शन किया जिसका परिणाम देश की जीत के रूप में सामने आया। विजय के लिये आवश्यक आत्मविश्वास से भरपूर नेतृत्व किया, उसके नेतृत्व में सभी खिलाड़ियों की आस्था, सही समय पर सही निर्णय, अच्छा समन्वय, लक्ष्य को पाने का संकल्प और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को राष्ट्रीय आकांक्षा में विलीन कर देने की विनम्रता के संतुलित संयोग ने ही देश को उल्लास का यह अवसर प्रदान किया है।

इसके विपरीत अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हुए देश को अलग-अलग दिशाओं में ले जाने की कोशिश करने वाला राजनैतिक नेतृत्व, अपने-अपने मंत्रालय में खेल करने में जुटे मंत्रीगण, इस खेल को बाहर से समर्थन दे रहे दलाल और मैच फिक्सर, उनके कारनामों पर लीपापोती करने और गठबंधन को मजबूरी मानने वाला उसका नेतृत्व, पूरे खेल पर आंखें मूंदे बैठी परमोच्च सत्ता और नफा-नुकसान के हिसाब से समर्थन-विरोध करने वाला विपक्ष देश को किस बेबसी की हालत में पहुंचा सकते हैं यह भी सबके सामने है।

संप्रग सरकार के दूसरे दौर में घोटालों की जो अटूट श्रंखला सामने आ रही है उसने देश के नागरिक को विचलित किया है। यहां की व्यवस्था में ही इस पतन के बीज छिपे हैं। अगर सारे घोटालों की राशि को जोड़ा जाय तो संभवतः वह देश के बजट से भी आगे निकल जाय। संसद में होने वाली नाटकीय बहस नागरिकों कोई समाधान दे पाने में असफल रही है। सत्तारूढ़ दल की भूमिका हास्यास्पद है तो प्रतिपक्ष की भूमिका संदेहास्पद।

यह स्थिति समाज में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और निराशा भरती है। समाज में सकारात्मक ऊर्जा लुप्त होने लगती है और अंधेरा काबिज हो जाता है। ऐसी स्थिति में हर दिन के अवसाद से बचने के लिये सामान्य लोग जीवन जीने के लिये जरूरी उत्साह जुटाने के प्रयास में उन विधाओं की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें क्षणिक ही सही, पर जीवन जीने के लिये आवश्यक उल्लास प्रदान करती है। क्रिकेट के मैच में मिलने वाली विजय ऐसा ही क्षणिक उल्लास देती है। लगभग ऐसा ही उल्लास लोग उन धारावाहिकों में ढूंढ़ते हैं जो मनोरंजन के नाम पर फूहड़ हास्य परोसते हैं।

किसी भी खेल को खेल भावना से ही लिया जाना चाहिये। इसका आशय है कि निरंतर अभ्यास से किसी खेल में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को यथोचित सम्मान मिले। अन्य खेलों में जहां दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाला खिलाड़ी भी रजत अथवा कांस्य पदक का हकदार होता है वहीं क्रिकेट में दूसरा स्थान पाने वाला पराजित माना जाता है, भले ही वह केवल एक रन से पीछे रहा हो। इस रूप में क्रिकेट खेल है ही नहीं।

यह संयोग ही है कि क्रिकेट का जन्म भी वहीं हुआ जहां आधुनिक लोकतंत्र का जन्म हुआ। भारत में यह वहीं से आया जहां से लोकतांत्रिक प्रणाली आयी। दोनों में ही यह अद्भुत साम्य है कि यहां एक कदम आगे रहने वाला विजेता माना जाता है और एक कदम पीछे रहने वाला पराजित। इसलिये एक छक्का लगा कर धोनी विजेता होते हैं और दस रन कम बना कर संगाकारा पराजित। यह वैसा ही है जैसे संसद में मत विभाजन पर एक वोट खरीद कर विजय पाने वाला दल सत्ता पर काबिज रहता है और देश को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो देने का अधिकार पा लेता है।

जहां तक देश की जनता का सवाल है, वह इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना चाहती है, पराजित होते देखना चाहती है। इसमें असफल रहने पर वह मनोवैज्ञानिक रूप से एक सैडिस्ट जैसा आचरण करती है और किसी को भी पराजित होते देखने में सुख का अनुभव करती है। अन्य खेलों में किसी को पराजित होते देखने का सुख नहीं है इसलिये उसे क्रिकेट ही सुहाता है। इसलिये ही उसे यह जानते हुए भी कि यह काल्पनिक है, हिन्दी फिल्मों में कानून को अपने हाथ में लेकर बड़े-बड़े गुण्डों को ठिकाने लगाता अभिनेता अच्छा लगता है। मन ही मन वह उन्हें अपना नायक मान लेता है।

क्रिकेट में जीत पर हर्ष का यह उबाल दिन-प्रति-दिन की व्यवस्थाजन्य असहायता पर जनसामान्य की टिप्पणी है। लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाकर सामने उपस्थित आपदा से मुंह मोड़ना लम्बे समय पर तक नहीं चल सकता। देश में भ्रष्टाचार के पहाड़ और असमानता की खाइयों का अस्तित्व जब तक है तब तक सुखी नागरिक जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। और बिना सुखी नागरिक जीवन सुनिश्चित किये कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान गठबंधन की मजबूरियों का राग अलाप कर जनता को भ्रमित नहीं कर सकता।

क्रिकेट में विजय का उन्माद तो जल्द ही ढ़ल जायेगा। इसके बाद फिर व्यवस्था की वास्तविकता से सामना शुरू होगा और एक-न-एक दिन व्यवस्था परिवर्तन की मांग जोर पकड़ेगी। अन्ना हजारे से लेकर बाबा रामदेव तक जिस अलख को जगाने में लगे हैं वह आम नागरिक तक पहुंचेगी और जल्दी ही नये भविष्य की इबारत लिखी जायेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रारंभ से ही व्यवस्था परिवर्तन की पक्षधर रही है। देश में परिवर्तन का जो आलोड़न-विलोड़न चल रहा है वह जब आकार लेगा तो अभाविप स्वाभाविक ही उसकी ध्वजवाहक बनेगी।

उदार नीतियां, बदहाल शिक्षा

संजय द्विवेदी

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय एक ऐसी लीलाभूमि है, जो नित नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है। वहां बैठने वाला हर मंत्री अपने एजेंडे पर इस तरह आमादा हो जाता है कि देश और जनता के व्यापक हित किनारे रह जाते हैं। अब कपिल सिब्बल के पास इस मंत्रालय की कमान है। उन्हें निजीकरण का कुछ ज्यादा ही शौक है।

वह अब लगे हैं कि किस तरह नए प्रयोगों से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए जाएं, किंतु इस तेज बदलाव के प्रयास के पीछे उनकी या मंत्रालय की सुचिंतित व स्पष्ट अवधारणा शायद ही है। बाजार को अच्छे लगने वाले परिवर्तन करके हम अपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र का कबाड़ा ही करेंगे, लेकिन लगता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन दिनों काफी उदार हो गया है। खासकर निजी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए उसके प्रयासों को इस नजर से देखा जा सकता है।

चिंता यही है कि उसके हर कदम से कहीं बाजार की शक्तियां मजबूत न हों और उच्च शिक्षा का वैसा ही बाजारीकरण न हो जाए जैसा हमने प्राथमिक शिक्षा का कर डाला है। किंतु लगता है कि सरकार ने वही राह पकड़ ली है। ताजा सूचना यह है कि प्रतिष्ठित संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने के कदमों के तहत प्रेसिडेंसी, सेंट जेवियर और सेंट स्टीफेंस जैसे कॉलेजों को यह छूट दी जाएगी कि वे अपनी डिग्री खुद दे सकें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लगता है कि इस कदम से विश्वविद्यालयों के भार में कमी आएगी। अब इसे कानून के जरिये लागू करने की तैयारी हो रही है।

कॉलेज अभी तक डिग्रियों के लिए विश्वविद्यालयों पर निर्भर रहते हैं। एनआर माधव मेनन समिति की सिफारिशों में विशेष शिक्षण स्वायत्तता पर जोर दिया गया है। जाहिर तौर पर यह कदम एक क्रांतिकारी कदम तो है, लेकिन इसके हानि और लाभों का भी आकलन किया जाना जरूरी है। कुछ बेहतर कॉलेजों को लाभ देने के लिए शुरू की जाने वाली यह योजना खराब कॉलेजों या सामान्य संस्थानों तक नहीं पहुंचेगी इसकी गारंटी क्या है? इसके खतरे बहुत बड़े हैं।

कॉलेजों की क्षमता का आकलन कौन करेगा यह भी एक बड़ा सवाल है। किस आधार पर सेंट स्टीफेंस बेहतर है और दूसरा बदतर। आखिर इस आकलन का पैमाना क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरह एक दूसरी बड़ी बात यह है कि इससे शासकीय विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा कम होगी और वे धीरे-धीरे एक स्लम में बदल जाएंगे। सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय बदहाली के शिकार हैं, किंतु हमारे मानव संसाधन मंत्री को विदेशी और निजी विश्वविद्यालयों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत में खुलवाने की जल्दबाजी है।

आखिर यह तेजी क्यों दिखाई जा रही है और कपिल सिब्बल इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? क्यों हम अपने पारंपरिक विश्वविद्यालयों की अकादमिक दशा व दिशा को सुधारने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं करते दिख रहे। आखिर इन्हीं संस्थाओं ने हमें योग्य प्रतिभाएं दी हैं, जो न केवल अपने देश में, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वारेन बफेट के मुताबिक अजीत जैन जैसे लोग सरकारी आइटीआइ से ही पढ़कर निकले हैं तो क्या इन संस्थाओं की प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है? जो हम इन्हें स्लम बनाने पर आमादा हैं।

शिक्षा का काम सरकार और समाज करे तो समझ में आता है किंतु पैसे के लालची व्यापारी

और कंपनियां अगर सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से आ रही हैं तो क्या हमें सतर्क नहीं हो जाना चाहिए। आए दिन खुल रहे नए-नए निजी विश्वविद्यालय अपनी चमक-दमक से सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को निरंतर चुनौती दे रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जिसमें निजी क्षेत्र को अपनी ताकत दिखाने का निरंतर अवसर है। कॉलेजों की स्वायत्तता एक ऐसा कदम होगा जिससे हमारे विश्वविद्यालय कमजोर ही होंगे और कॉलेजों पर नियंत्रण रखने का उपाय हमारे पास आज भी नहीं है।

कम से कम विश्वविद्यालय से संबद्धता के नाम पर कुछ नियंत्रण बना और बचा रहता है, लेकिन अब वह भी खत्म होने के कगार पर है। इसे बचाने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी कोई समानांतर व्यवस्था बनाई जाए जो इन कॉलेजों का नियमन कर सके। किंतु वह व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से मुक्त होगी इसमें फिलहाल संदेह ही है। आप कुछ भी कहें हमारी ज्यादातर नियामक संस्थाएं आज भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन गई हैं। निजीकरण की तेज हवा ने इस भ्रष्टाचार को एक आंधी में तब्दील कर दिया है।

विभिन्न कोर्सेज की मान्यता प्रदान करने के लिए ये नियामक संस्थाएं कैसे और कितने तरह का भ्रष्टाचार करती हैं इसे निजी क्षेत्र के शिक्षा कारोबारियों से जाना जा सकता है। हालांकि अंततः इसका फल बेचारे अभिभावक और छात्र ही भुगतते हैं, क्योंकि यह सारा धन तो अंततोगत्वा उसकी जेब से ही वसूला जाता है।

अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वाली हमारी लोक कल्याणकारी सरकारें भले ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश और विदेशी निवेश के लिए लाल कालीन बिछाने पर आमादा हों, लेकिन इससे उच्च शिक्षा एक खास तबके तक शायद सीमित होकर रह जाएगी। यह गंभीर चिंता का विषय है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक निरंतर निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों को बनाने में लगी हैं और अपने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की चिंता उन्हें शायद ही है। सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन इसकी चिंता राज्यों की सरकारों को नहीं है। जनता की जिम्मेदारी से जुड़े हर काम से अपना हाथ खींचकर सरकारें सारा कुछ बाजार को सौंपने पर आमादा हैं, जिसके कारण को समझना फिलहाल एक मुश्किल काम है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र पूरी तरह बाजार के हवाले हो चुके हैं।

क्या इस तरह के कामों से एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मजाक नहीं बनाया जा रहा है। यह समझ में नहीं आने वाली बात है कि एक व्यापारी अपने ब्रांड का विस्तार करता है और उसका संरक्षण भी करता है किंतु हमारी सरकारें अपने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों को उजाड़ने में लगी हैं। ऐसे में आम आदमी के सामने विकल्प क्या बचता है।

महंगी शिक्षा और महंगा इलाज क्या एक लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा से मेल खाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को मजबूत करते हुए हम क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या वास्तव में हमने अपने जनतंत्र को एक मजाक बनाने की ठान ली है और हमारे पास दूसरे कोई विकल्प नहीं हैं। कुल मिलाकर सारी कवायद कुछ निजी कॉलेजों को ताकत देने का तक ही सीमित लगती है। इसमें व्यापक हितों की अनदेखी की जा रही है।

सरकार जिस तरह निजी क्षेत्र पर मेहरबान है उसमें कुछ भी संभव है, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी के लिए उच्च शिक्षा का क्षेत्र आने वाले दिनों में एक सपना हो जाएगा। इससे समाज में तनाव और विवाद की स्थितियां ही बनेंगी। केंद्र सरकार कॉलेजों को स्वायत्तता देने के सवाल पर थोड़ी संजीदगी दिखाए, क्योंकि इसके कई खतरे हैं। पूरे मसले पर व्यापक विमर्श के बाद ही कोई कदम उठाना उचित होगा, क्योंकि यह सवाल आम लोगों के भविष्य से भी जुड़ा है।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़े हैं)

छात्राओं के शोषण में शिक्षकों की संलिप्तता दुर्भाग्यपूर्ण

मध्य प्रदेश के खण्डवा कृषि महाविद्यालय में गत ९ मार्च २०११ को विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन के दौरान छात्राओं से दुर्व्यवहार के आरोपी प्रोफेसर अशोक चौधरी द्वारा प्रतिनिधिमण्डल से अभद्र व्यवहार किये जाने के बाद छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उनके मुख पर कालिख पोत दी गयी।

घटना को राजनैतिक रंग देने की कोशिश की गयी। यह राजनीति तब और गहरा गयी जब घटना के दो दिन बाद महाविद्यालय के ही एक अन्य प्राध्यापक श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गयी। कांग्रेस ने शिक्षा परिसरों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने का समर्थन करने के बजाय इसे सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर कृषि महाविद्यालय से स्थानांतरित होकर खण्डवा आये प्रोफेसर अशोक चौधरी पर शराब पीकर महाविद्यालय में आने और छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप थे। उन पर छात्रावास की एक छात्रा के साथ अनैतिक संबंध रखने के भी आरोप लगे थे तथा उक्त छात्रा द्वारा भी अन्य छात्राओं को प्रोफेसर का नाम लेकर प्रताड़ित किया जाता था। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अनेक बार मौखिक अथवा लिखित शिकायत किये जाने के बावजूद छात्रावास वार्डन तथा संकायाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। अभाविप द्वारा भी इस संबंध में कॉलेज प्रशासन से कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था जिस पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

इसके विपरीत छात्राओं को प्रयोगात्मक परीक्षाओं में फेल करने की धमकियां दी जाने लगी तथा प्रोफेसर से निकट सम्बंध रखने वाली छात्रा द्वारा अन्य छात्राओं से दुर्व्यवहार बढ़ता ही गया।

छात्राओं के आग्रह पर विद्यार्थी परिषद के स्थानीय कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमण्डल कॉलेज प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर कॉलेज पहुंचा। जब संकायाध्यक्ष से बात चल ही रही थी तभी प्रो. अशोक चौधरी शराब के नशे में वहां आये और प्रतिनिधि मण्डल में शामिल छात्राओं को गालियां देने लगे। इस पर विवाद प्रारंभ हो गया तथा मामले के तूल पकड़ने पर छात्राओं ने उनके मुंह पर कालिख पोत दी।

इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात भी प्रशासन ने प्रो. अशोक चौधरी को बचाने की कोशिश की। परिषद के प्रतिनिधिमण्डल के विरुद्ध जहां अभियोग दर्ज किया गया है वहीं आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गयी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मध्य प्रदेश के शिक्षा परिसरों में छात्राओं के असुरक्षित होने की बात कहते हुए मामले की जांच के लिये आयोग बनाने तथा विश्वविद्यालयों में महिला प्रकोष्ठ गठित किये जाने की मांग सरकार से की है।

अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विष्णुदत्त शर्मा के अनुसार छात्राओं के शोषण के मामलों में सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली पहलू अधिकांश प्रकरणों में शिक्षकों की संलिप्तता है।

प्रदेश मंत्री भारती कुंभारे ने राज्य सरकार से मांग की है कि छात्राओं की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों का पक्ष लेने वाले भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने राज्य सरकार पर शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज में छात्राओं को छेडने और उनके साथ अश्लील हरकत करने वाले प्राध्यापकों की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूजा नहीं करेगी। ऐसे प्राध्यापकों के खिलाफ अभाविप अभियान चलाएगी।

तकनीकों पर भारी कुदरत का कहर

स्वाती जैन

अब तक विश्व में अनेकों आपदायें आई है लेकिन हाल ही में जापान में आई आपदा और उसके बाद जो भीषण त्रासदी देखने को मिली वह हमें एक चेतावनी देती प्रतीत होती है। यह चेतावनी हमें आने वाले खतरों का विकराल रूप स्पष्ट करती दिख रही है। एक ओर तो जहां इस त्रासदी ने वैज्ञानिक विकास पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, वहीं दूसरी ओर बचाव के नाम पर निर्मित तकनीकों की मौजूदगी पर भी ज़ोरदार तमाचा मारा है। जापान में भूकंप और सुनामी के कहर के चलते लगभग दस हजार लोगों की मृत्यु और ३०० अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।

जापान में अरबों डॉलर के ढ़ांचागत नुकसान के साथ ही हजारों लोग आज भी लापता हैं। यह दृश्य किसी भयानक हॉलीवुड फिल्म की शुरुआत की तरह लगता है और फिल्म भी ऐसी जिसमें इंसानों की रक्षा करने वाला कोई सुपरहीरो नहीं है, बस है तो सिर्फ तबाही का गहरा और जानलेवा मंज़र। जापान में आये भूकंप और सुनामी से क्षतिग्रस्त इमारतों को तो फिर से निर्मित किया जा सकता है लेकिन परमाणु विकिरण के चलते जो रोग और बीमारियां नागरिकों को जकड लेंगी उनसे बच पाना असंभव है।

परमाणु विकिरण के चलते हवा पानी तक अशुद्ध हो जाएँगे तो फिर ऐसी परिस्थितियों में जीवित मानव शरीर भी ऐसा होगा जैसे किसी बंजर ज़मीन पर उगा वृक्ष। ये रेडियोधर्मी तरंगे तो आने वाली कई पीढ़ियों की ज़िन्दगी को अंधकारमय करने में सक्षम हैं।

जापान जैसे विकसित देश में जहां भूकंप और सुनामी से बचने के लिए एक अच्छी और मजबूत बचाव प्रणाली है तो फिर क्यों इस बार इस प्रणाली ने कुदरत के कहर के सामने घुटने टेक दिए। तकनीक संपन्न जापान में जब ऐसी आपदायें कोहराम मचा सकती हैं तो फिर भारत जैसे देशों की तो बिसात ही क्या जहां बचाव के तरीकों पर आपदा आने के बाद विचार किया जाता है।

जापान में आई यह जानलेवा आपदा हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा कर रही है और यह प्रश्न है कि क्या जापान में मची यह तबाही सच में कुदरत का प्रकोप थी या फिर इंसानों द्वारा प्रकृति के शोषण का परिणाम है। प्रकृति और प्रोद्योगिकी की इस जंग में एक बार फिर प्रकृति ने बाज़ी मारी है और नतीजा फिर से वही निकला है जो २००१ में गुजरात में भूकंप के रूप में था और २००४ में सुनामी के रूप में।

इस बार जापान की आपदा ने सम्पूर्ण विश्व को भविष्य का भयानक चित्र दिखा दिया है। इस चित्र में परमाणु संयंत्रों के विकास पर उंगली उठाई गयी है। जापान के संयंत्रों में हुआ परमाणु रिसाव आज कनाडा और ब्रिटेन तक फैल चुका है। जापान तो आज तक हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोटों का ही दंश झेल रहा था ऐसे में कुदरत के इस कहर के चलते एक बार फिर जापानी नागरिकों और उनकी भावी पीढ़ियों पर आंशिक मौत का खतरा मंडरा रहा है।

जापान का ढ़ांचागत विकास तो दोबारा मुमकिन है लेकिन लोगों के मन में समा चुके कुदरत के इस डर से निजात पाना मुश्किल होगा। जापान की रक्षानीति में चार चाँद लगा देने वाले परमाणु संयंत्र आज उसके स्वयं के गले की फांस तो बन ही गए हैं, साथ ही पूरी दुनिया को भी अपनी चपेट में लेने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं।

इस आपदा ने जापान की विकसित अर्थव्यवस्था की जो बखिया उधेडी है वह निश्चित ही अन्य देशों को प्रकृति के प्रति अपने संबंधों के बारे में सोचने-विचारने पर मजबूर कर देगी। अब केवल हाथ में झंडे लेकर वन लगाओ का नारा लगाना ही काफी नहीं है बल्कि परमाणु संयत्रों की संख्या और उन पर मानव की निर्भरता को कम करना भी जरुरी है।

राधिका तंवर हत्याकांड

परिषद के आह्वान पर परिसर बंद

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राधिका तंवर की हत्या से गुस्साए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और डूसू द्वारा आयोजित बंद का असर नॉर्थ व साउथ कैंपस में खासा दिख रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस में एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया।

एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रोहित चहल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी अब अपराध की राजधानी बनकर रह गई है। लगातार हो रही हिंसक वारदातों ने दिल्ली सहित पूरे एनसीआर को हिलाकर रख दिया है और प्रशासन है कि अपनी नींद से जगने का नाम ही नहीं ले रहा है।

दिल्ली वि.वि. बंद के लिए खासतौर पर दो टीमों को लगाया गया था। दक्षिणी परिसर की कमान छात्राओं ने संभाली। डूसू उपाध्यक्ष प्रिया व सचिव नीतू डबास के नेतृत्व में यहां स्थित रामलाल आनंद, मोतीलाल, आत्मा राम सनातन धर्म और श्री वैंकटेश्वर कहलेज बंद कराए गए। उत्तरी परिसर में डूसू अध्यक्ष व एबीवीपी के अन्य पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाला।

दक्षिणी परिसर में बंद की शुरुआत रामलाल आनंद कॉलेज से सुबह नौ बजे हुई। दोपहर १२ बजे तक श्री वैंकटेश्वर कॉलेज के साथ समूचा कैम्पस बंद हो चुका था। उधर उत्तरी परिसर में रामजस कॉलेज से शुरू हुआ अभियान क्रांति चौक पर प्रदर्शन के साथ खत्म हो गया।

रोहित चहल ने बताया कि इस दौरान रामजस, हिन्दू व हंसराज कॉलेज में चल रही कक्षाओं को बंद कराने में शिक्षकों की खूब मदद मिली जबकि किरोड़ीमल कॉलेज में पहले से ही कक्षाएं बन्द कर दी गयी थीं।

ज्ञातव्य है कि एबीवीपी और डूसू ने दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन किया और प्रशासन व सरकार का पुतला भी फूंका।

अभाविप और छात्रसंघ के आह्वान पर राधिका तंवर हत्याकांड के विरोध में शुक्रवार को आयोजित डीयू बंद को छात्र ही नहीं, शिक्षकों का भी भरपूर समर्थन मिला। कक्षाएं बंद कराने पहुंचे छात्रों की बात सुनने के बाद शिक्षकों ने भी स्टाफ रूम की राह पकड़ ली। दक्षिणी परिसर की तरह उत्तरी परिसर में भी बंद का जबर्दस्त असर दिखा।

विदित हो कि नारायणा की रहने वाली राधिका तंवर (२०) डीयू के साउथ कैंपस स्थित रामलाल आनंद कॉलेज में बीए प्रोग्रामिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। मंगलवार को सत्य निकेतन बस स्टाप पर उतरने के बाद वह फुट ओवरब्रिज से होते हुए कॉलेज की तरफ जा रही थी। तभी सुबह करीब १०.२५ बजे एक युवक ने पीछे से उसकी पीठ में गोली मार दी थी। इससे राधिका की मौके पर ही मौत हो गई थी।

शहीदों की कुर्बानी से मिली आजादी

फरीदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् फरीदाबाद इकाई द्वारा २३ मार्च को शहीद दिवस के मौके पर शहीदों को समर्पित प्रतिभा सम्मान समारोह उडान २०११ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर परिषद की ओर से जिले भर की १४० प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला उपायुक्त डा. प्रवीन कुमार आईएएस, एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीनिवास, विशिष्ट अतिथि नगर निगम पार्षद धीरेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ट अधिवक्ता भंवर सिंह भाटी मौजूद थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी राजेंद्र जैन ने की। कार्यक्रम की शुरूआत परिषद् गीत से हुई। जिसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्जलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त डा. प्रवीन कुमार ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव मात्र कुछ युवा नहीं थे, बल्कि वे एक पूरी विचारधारा थे। जो अंतिम छोर तक आदमी की मूलभूत सुविधा के लिए लडे। युवाओं को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। युवा वर्ग को पूरी ईमानदारी से अध्ययन कर विचार को अपनाना चाहिए। मुख्य वक्ता एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि परिषद का उद्देश्य छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में संगठित करना है। परिषद् छात्र को कैरिअर के साथ समाज के लिए कैसे जिया जा सकता है, यह सिखाती है। परिषद् अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास कर उसे समाज कार्य के लिए तैयार करती है। पूर्व राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने २०२० में भारत को महाशक्ति बनाने का सपना देखा है जो युवा और छात्रों के कंधों पर टिका हुआ है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पार्षद धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज के भौतिक वातावरण में हर व्यक्ति भगत सिंह बनने से परहेज करता है। जबकि भगत सिंह उसके अन्दर स्वयं में छिपा हुआ है। जबकि वरिष्ट अधिवक्ता भंवर सिंह भाटी ने संस्कारवान छात्र ही समाज और देश की धरोहर बताया।

प्रतिभा सम्मान समारोह में स्कूल, कालेज में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पाने वाले ६०, खेल के सात और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले छात्रों, अध्यापक, वकील और युवा सरपंचों सहित कुल १४० लोगों को सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मोर्चा परिषद् के सह जिला संयोजक गौरव ठाकुर ने संभाला, जबकि मंच संचालन जिला छात्रा प्रमुख कुमारी सोनी और धन्यवाद ज्ञापन जिला

'छात्रशक्ति' कार्यालय का लोकार्पण

संयोजक राहुल यादव ने किया।

भोपाल में २८ मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय "छात्र शक्ति" का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

श्री भागवत ने लोकार्पण करते हुए कहा कि किसी कार्य को करने का तत्व रहता है, ध्येय रहता है। इसके लिए कार्यक्रम होते हैं, कोष की व्यवस्था होती है और उक्त सभी कार्यक्रम ठीक से चलाने के लिए कार्यालय होता है इसलिए तत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए अन्यथा समस्याएं सामने आती हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थी परिषद की भूमिका की सराहना की।

अध्यक्षीय उद्‌बोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह यहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यार्थी परिषद की पहल पर मुख्यमंत्री निवास पर छात्र पंचायत आयोजित करने की भी घोषणा की।

कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय संगठन मंत्री विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि कार्यालय की कल्पना स्व. श्री शालिगराम तोमर ने की थी। श्री विष्णुदत्त ने कार्यालय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय तकनीकी और सर्वसुविधायुक्त है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए अध्ययन, कम्प्यूटर एवं लाइब्रेरी की सुविधा निःशुल्क होगी। इस कार्यालय को एजुकेशन एवं इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया जाएगा।

विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने बताया कि कार्यालय का उपयोग आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को राष्ट्र और समाज के लिए उनकी योग्यता व क्षमता को निखारने एवं प्रेरणा देने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को दृष्टिकोण, जानकारी, विचार, व प्रेरणा देने का कार्य इसी कार्यालय से होगा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए इसके द्वार २४ घण्टे खुले रहेंगे।

कार्यालय के लोकार्पण समारोह के पहले अभाविप के पूर्व कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी संपन्न हुआ। इसके साथ ही नवनिर्मित कार्यालय भवन में स्व. शालिगराम जी तोमर के नाम पर पुस्तकालय भी बनाया गया। कार्यक्रम में वनवासियों द्वारा ढोलक एवं वाद्य यंत्रों की थाप पर प्रस्तुत किये गये मनभावन लोकनृत्य भी हुआ।

जम्मू-कश्मीर

रक्तदान शिविर का आयोजन

जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने जम्मू कश्मीर में २५ मार्च २०११ को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह शिविर २३ मार्च १९३१ को देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया गया था। जम्मू विश्वविद्यालय परिसर में इस कार्यक्रम में लगभग ४४ यूनिट ब्लड एकत्र किया गया।

एबीवीपी इस तरह के शिविर का आयोजन प्रत्येक वर्ष करती आई है जिसका उद्देश्य युवाओं में भाईचारा, देशप्रेम ओर राष्ट्रप्रेम की भावना को जगाना है।

एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने स्वागत करते हुए एबीवीपी के उद्देश्य तथा लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों का आयोजन करके वहां के लिए समाज के प्रति युवाओं की भूमिका को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। हम इस मिट्टी के शहीद भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे महान बेटों के बलिदान को याद करना चाहते हैं।

मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में इस अवसर पर एस. नरिंदर सिंह (अध्यक्ष एसकेएयुएसटी शिक्षक संघ) और डॉ. टी. आर. रैना (ब्लड बैंक जीएमसी के प्रमुख) जैसे व्यक्तित्व वाले अधिकारी उपस्थित थे। प्रोग्राम पारंपरिक दीप

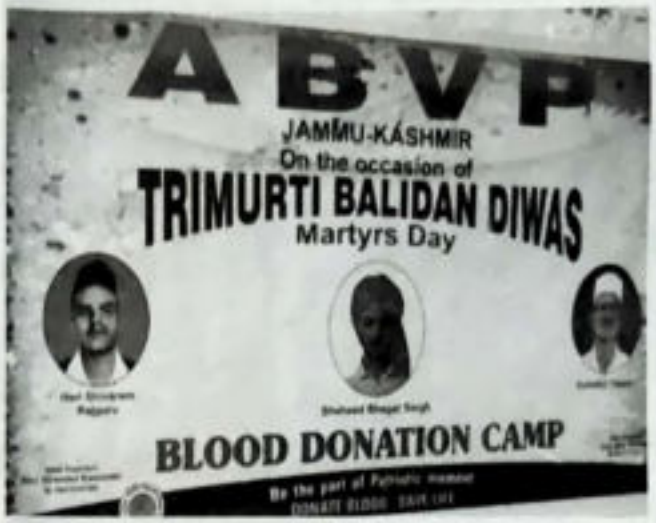

प्रज्ज्वलन के साथ शुरू किया गया और भारत के महान शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई।

एस नरिंदर सिंह ने शिक्षकों, छात्रों और जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्वानों सहित सभा को संबोधित करते हुए युवाओं को सामाजिक कार्यों, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समुदाय में सक्रिय भाग लेने के लिए कहा ताकि भारत दुनिया में पहले स्थान पर पहुँच सके। उन्होंने आज के परिदृश्य भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अपराध, नशा, पश्चिमी संस्कृति का बुरा प्रभाव की तुलना भगत सिंह के उस दौर से की। उन्होंने कहा कि आज इस तरह के बलिदान की जरूरत नहीं बल्कि एक सतर्क, जागरूक, वफादारी तथा बल की जरूरत है।

डॉ. टी.आर. रैना ने एबीवीपी को उनके २० वर्षों से किये जा रहे आयोजन के लिए सराहा। भाग लेने वाले युवाओं को बधाई भी दी और साथ ही उन्होंने रक्तदान और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बताया।

मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक से डा. मीणा सिद्धू, डॉ. मीतू, श्री सुरेंदर , सुश्री अंजू और श्री नरेन्द्र शर्मा ने भी एबीवीपी के इस सफल आयोजन में अपना सहयोग दिया।

विद्यार्थी परिषद् ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, २३ मार्च। शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ८०वें बलिदान दिवस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कैम्पस के अन्य छात्रों ने भी शहीदों के बलिदान को नमन कर पुष्प चढ़ाए।

श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव नीतू डबास, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री धर्मेन्द्र धामू, उत्तरी विभाग के संगठन मंत्री दीपक पाठक सहित कई छात्र भी उपस्थित रहे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा परिषद ने नजफगढ़ क्षेत्र में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें छात्रों के साथ-साथ युवा व आम लोगों ने भी भाग लिया। इस दौरान परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. योगेन्द्र पयासी एवं प्रदेश मंत्री रोहित चहल भी उपस्थित रहे।

सभा को संबोधित करते हुए चहल ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज के युवकों के लिए एक आदर्श है। भगत सिंह के उदय से स्वतंत्रता संघर्ष को नई गति मिली।

महिला दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन

९ मार्च, गाजियाबाद। एबीवीपी ने विश्व महिला दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की और छात्राओं से आह्वान किया कि वह जागरूक बने और पूरे समाज को जागरूक बनाएं।

गोष्ठी में मुख्य वक्ता परिषद की दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष निहारिका शर्मा ने कहा कि महिला समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसमें चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर सेना, पुलिस, राजनीति का क्षेत्र वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देश व समाज की रक्षा के लिए वह अपने दायित्वों को अच्छे से निभा रही हैं। भारतीय परंपरा में नारी को शुरू से ही पूजनीय माना गया है। उसकी कभी शक्ति तो कभी सौम्या के रूप में पूजा की जाती है। परंतु आज सभ्य समाज में जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है उसे हम सबको मिलकर रोकना होगा।

गोष्ठी में संध्या शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान कर रही हैं उसे देखकर लगता है कि महिलाएं अब खुद सक्षम हो गई हैं। यह कहीं न कहीं महिला सशक्तीकरण का ही परिणाम है कि वह अब जागरूक हो रही हैं। यह राष्ट्रहित के लिए अच्छी बात है। जब महिलाएं सशक्त बनेंगी पूरा समाज आगे बढ़ेगा। छात्राओं को चाहिए कि वह पढ़ाई के दौरान ही अपनी रुचि के मुताबिक प्रोफेशन चुनें।

उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन

भोपाल। पिछले दिनों जबलपुर में चिकित्सा छात्राओं को अच्छे अंक दिए जाने के एवज में अनैतिक कार्य के लिए मजबूर किए जाने का मामला सामने आने के बाद से राज्य के शिक्षा जगत में हड़कंप मचा हुआ है। इस प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा से मुलाकात कर गुरुवार को ज्ञापन भी सौंपा था।

अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री को स्कैंडल की पूरी जानकारी दी गई। एबीवीपी ने आरोपी परीक्षा नियंत्रक राणा और डिप्टी रजिस्ट्रार काकोडिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। साथ ही मेडिकल कॉलेज की प्राध्यापक डॉ. मीता श्रीवास्तव और तथाकथित छात्रनेता राजू खान द्वारा विश्वविद्यालय में कराए गए निर्माणों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करवाने की मांग भी की गई।

उच्च शिक्षा मंत्री ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच के साथ इस मामले में संलिप्त पाए गए दो अधिकारियों उप सचिव परीक्षा रवींद्र काकोडिया और परीक्षा नियंत्रक एसएस राणा को निलम्बित करने के निर्देश दिए थे। इस प्रकरण में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव रवीन्द्र काकोडिया और परीक्षा नियंत्रक एस. एस. राणा को निलंबित कर दिया गया है। ये दोनों जबलपुर मेडिकल कॉलेज स्कैंडल में आरोपी हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने इसके निर्देश गुरूवार को दिए। शर्मा ने कहा है कि विभागीय स्तर पर भी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई कराई जाएगी।

इस प्रकरण में नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर और नेत्र रोग विभाग की प्रमुख डॉ. मीता श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। मेडिकल कॉलेज की पूर्व हॉस्टल वॉर्डन डॉ.मीता पर किस्मत के बदले अस्मत मांगने के मामले को दबाने का आरोप है।

गौरतलब है कि राजू खान एक ठेकेदार है, जो वर्षों से मेडिकल कॉलेज में सक्रिय है। मेडिकल कॉलेज की दो सीनियर छात्राओं के नाम भी इस मामले में आए हैं। बताया गया है कि ये छात्राएं राजू खान के लिए काम करती थीं और मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को पास कराने के नाम पर कतिपय व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती थीं। अभाविप ने रानी दुर्गावती विवि और मेडिकल कॉलेज जबलपुर की छात्रा को पास कराने के नाम पर अस्मत लेने के स्कैंडल के मुद्दे को गंभीरता से उजागर करते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

परीक्षा तिथि बढ़ाने को लेकर धरना

मुजफ्फरपुर, १४ मार्च। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने को बीआरए बिहार वि.वि. के प्रशासनिक गेट पर धरना दिया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये परिषद् के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रांतीय संगठन मंत्री रामाशंकर सिन्हा, विवि संगठन मंत्री अनिल कुमार समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न महाविद्यालयों में वर्ग संचालन के अभाव में छात्र-छात्राओं के करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। धरना को संबोधित करने के उपरांत अभाविप के प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों की समस्याओं से संबंधित प्रतिकुलपति डा. पद्माशा झा को मांग पत्र सौंपा।

संगठन के दबाव के बाद पर प्रतिकुलपति ने परीक्षा तिथि बढ़ाने के संकेत दिए हैं। स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों व अभाविप कार्यकर्ताओं ने इसके पूर्व परीक्षा नियंत्रक से मिलकर परीक्षा तिथि बढ़ाने की गुहार लगाई थी।

युवा और राजनीति

विजय कुमार

राजनीति में युवाओं की भूमिका कैसी हो, इस पर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने विभिन्न माध्यमों से युवा पीढ़ी से सम्पर्क किया। विश्वविद्यालयों में जाकर उन्होंने युवाओं से राजनीति को अपनी आजीविका (कैरियर) बनाने को कहा पर उनका यह विचार कितना समीचीन है, इस पर विचार आवश्यक है।

यह तो सच ही है कि भारत एक युवा देश है। पिछले लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई में युवा होने के कारण राहुल भारी पड़े। यद्यपि पर्दे के आगे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं पर सरकार में सबसे अधिक सोनिया और राहुल की ही चलती है। राहुल की इस सफलता से सब दलों को अपनी सोच बदलनी पड़ी। सबसे बड़े विपक्षी दल भाजपा ने तो अपना अध्यक्ष ही ५२ वर्षीय नितिन गडकरी को चुन लिया। अब सब ओर युवाओं को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। भावी राजनीति के एजेंडे पर निःसंदेह अब युवा आ गये हैं।

युवाओं का राजनीति से जुड़ना और उसे आजीविका बनाना दोनों अलग-अलग बातें हैं पर राहुल गांधी दोनों को एक साथ मिलाकर भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीति नौकरी, व्यवसाय या खेती की तरह आजीविका नहीं है। नौकरी शैक्षिक या अनुभवजन्य योग्यता से मिलती है, जबकि खेती और व्यापार प्रायः पुश्तैनी होते हैं। यद्यपि कांग्रेस और उसकी देखादेखी अधिकांश दलों ने राजनीति को भी पुश्तैनी बना लिया है पर यह सैद्धान्तिक रूप से गलत है। प्रत्याशी भी चुनाव में हाथ जोड़कर वोट मांगते समय यही कहते हैं कि इस बार हमें सेवा का अवसर दें। जनता किसे यह अवसर देती है, यह बात दूसरी है पर इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति आजीविका न होकर समाज सेवा का क्षेत्र है।

भारतीय लोकतंत्र एवं संविधान लगभग ब्रिटिश व्यवस्था की नकल है। उसी के अनुरूप यहां जन प्रतिनिधियों को वेतन तथा अन्य भत्ते दिये जाते हैं। जन प्रतिनिधि लगातार अपने क्षेत्र में घूमते हैं। सैकड़ों लोग उनसे मिलने हर दिन आते हैं, जिनके चाय-पानी में बड़ी राशि व्यय होती है। यह राशि सरकार दे, इसमें आपत्ति नहीं है पर राजनीति किसी के घर चलाने का एकमात्र साधन बन जाए यह नितांत अनुचित है।

राजनीति में उतार-चढ़ाव आते ही हैं। लोग चुनाव हारते और जीतते रहते हैं। यदि राजनीति ही आजीविका का एकमात्र साधन होगी, तो चुनाव हारने पर व्यक्ति अपना घर कैसे चलाएगा? यह बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे किसी की नौकरी छूट जाए, या उसे व्यापार में घाटा हो जाए या खेती धोखा दे जाए। ऐसे में व्यक्ति अपने मित्रों, परिजनों या बैंक के कर्ज आदि से फिर काम को जमा लेता है पर राजनीति में तो ऐसा सहयोग नहीं मिलता। फिर उसके परिवार का क्या होगा? या तो वह चोरी-डकैती करेगा या आत्महत्या। और यह दोनों ही अतिवादी मार्ग अनुचित हैं।

एक दूसरे दृष्टिकोण से इसे देखें। यदि सब जन प्रतिनिधि युवा ही बन जाएं, तो भी कुल मिलाकर कितने युवा आजीविका पा सकेंगे? लोकसभा, राज्यसभा, देश भर की विधानसभा और विधान परिषद को मिला कर संभवतः १० हजार स्थान बनते होंगे। यदि इसमें जिला और नगर पंचायतों के प्रतिनिधि मिला लें, तो संख्या २५ हजार होगी। यदि इसमें देश की ५ लाख ग्राम पंचायतें और जोड़ लें, तो यह संख्या सवा पांच लाख हो जाएगी। यदि हर युवा राजनीति को ही आजीविका बनाने की सोच ले, तो शेष ४०.४५ करोड़ युवा

क्या करेंगे?

कौन नहीं जानता कि राजनीति और चुनाव का चस्का एक बार लगने पर आसानी से छूटता नहीं है। व्यक्ति चाहे हारे या जीते पर वह इस क्षेत्र में ही बना रहना चाहता है। आजकल राजनीति पूर्णकालिक काम हो गयी है। इसमें अत्यधिक पैसा खर्च होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति भ्रष्ट साधन अपनाता है। इसीलिए स्थानीय नेता प्रायः ठेकेदारी करते मिलते हैं। इस दो नंबरी धंधे से वे एक झटके में लाखों-करोड़ों रु. पीट लेते हैं। कई नेता एन.जी.ओ. बनाकर सेवा के नाम पर घर भरते हैं। क्या राहुल गांधी ऐसे ही भ्रष्ट युवाओं की फौज देश में तैयार करना चाहते हैं?

यदि किसी को भ्रम हो कि युवा लोग भ्रष्ट नहीं होते, तो राजीव गांधी को देख लें। प्रधानमंत्री बनते ही देश ने उन्हें 'मिस्टर क्लीन' की उपाधि दी थी। उन्होंने कांग्रेस को सत्ता के दलालों से दूर करने का आह्वान किया था। सबको लगा था कि राजनीतिक उठापटक से दूर रहा यह व्यक्ति सचमुच कुछ अच्छा करेगा। इसीलिए सहानुभूति लहर के बीच जनता ने उन्हें संसद में तीन चौथाई बहुमत दिया पर कुछ ही समय में पता लग गया कि वह भी उसी भ्रष्ट कांग्रेसी परम्परा के वाहक हैं, जिस पर उनके नाना, मां और आम कांग्रेसी चलते रहे हैं। मिस्टर क्लीन बोफोर्स दलाली खाकर अंततः 'मिस्टर डर्टी' सिद्ध हुए।

अपनी अनुभवहीनता और देश की मिट्टी से कटे होने के कारण राजीव गांधी के अधिकांश निर्णय नासूर सिद्ध हुए। उन्होंने ही अंग्रेजीकरण को अत्यधिक बढ़ावा दिया, जिससे ग्राम्य प्रतिभाओं के उभरने का मार्ग सदा को बंद हो गया। पहले गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पाठशाला में भेजकर संतुष्ट रहता था पर आज अंग्रेजी बोलने वाले ही नौकरी पा सकते हैं। इसलिए अपना पेट काटकर भी लोग बच्चों को महंगे अंग्रेजी विद्यालय में भेजने को मजबूर हैं। अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण भारत में स्थानीय भाषा और बोलियों का मरना जारी है। यह सब राजीव गांधी की ही देन हैं।

विदेश नीति के मामले में भी राजीव गांधी अनाड़ी सिद्ध हुए। उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेसी प्रभाव बढ़ाने के लिए श्रीलंका में लिट्टे को बढ़ावा दिया, पर जब लिट्टे सिर पर सवार हो गया तो उन्होंने वहां शांति सैनिकों को भेज दिया। इससे भारत के सैकड़ों सैनिक मारे गये और विश्व भर में हमारी थू-थू हुई। श्रीलंका जैसे मित्र देश की एक बड़ी जनसंख्या के मन में भारत के प्रति स्थायी शत्रुता का भाव पैदा हो गया। राजीव की हत्या भी इसीलिए हुई। स्पष्ट है कि राजनीति में यौवन की अपेक्षा देश-विदेश के मामलों का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है।

लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि युवा पीढ़ी राजनीति से अलिप्त हो जाए? उसे देश के वर्तमान और भविष्य से कुछ मतलब ही न हो? यदि ऐसा हुआ, तो यह बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए उन्हें भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। पर उनकी सक्रियता का अर्थ सतत जागरूकता है। ऐसा हर विषय, जो उनके आज और कल को प्रभावित करता है, उस पर वे अहिंसक आंदोलन कर देश, प्रदेश और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपनी नीति और नीयत बदलने पर मजबूर कर दें। ऐसा होने पर हर दल और नेता दस बार सोचकर ही कोई निर्णय लेगा।

स्वाधीनता के आंदोलन में हजारों युवा पढ़ाई छोड़कर कूदे थे। क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू, आजाद आदि राजनीतिक रूप से निष्क्रिय थे, क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? १९४८ में गांधी हत्या के झूठे आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध के विरुद्ध लगभग ७० हजार स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। उनमें से अधिकांश युवा थे। १९७४-७५ में इंदिरा गांधी के भ्रष्ट प्रशासन, आपातकाल और फिर संघ पर प्रतिबंध के विरुद्ध भी एक लाख लोग जेल गये। सत्तर के दशक में असम में घुसपैठ विरोधी आंदोलन हुआ। श्रीराम मंदिर आंदोलन में लाखों हिन्दुओं ने कारावास स्वीकार किया। यद्यपि इनमें से दस-बीस लोग सांसद और विधायक भी बने पर क्या शेष लोग राजनीतिक रूप से निष्क्रिय माने जाएंगे, चूंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा?

स्पष्ट है कि राजनीतिक सक्रियता का अर्थ चुनाव लड़ना नहीं, सामयिक विषयों पर जागरूक व आंदोलनरत रहना है। बहुत से लोगों के मतानुसार वोट देने की अवस्था भले ही १८ वर्ष कर दी गयी हो पर चुनाव लड़ने की अवस्था ५० वर्ष होनी

चाहिए। जिसे नौकरी, खेती, कारोबार और अपना घर चलाने का ही अनुभव न हो जिसने जीवन के उतार-चढ़ाव न देखें हों, वह अपने गांव, नगर, जिले, राज्य या देश को कैसे चला सकेगा?

भारतीय जीवन प्रणाली भी इसका समर्थन करती है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बाद २५ वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम समाज सेवा को ही समर्पित है। इस समय तक व्यक्ति अपने अधिकांश घरेलू उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है। उसे दुनिया के हर तरह के अनुभव भी हो जाते हैं। काम-धंधे में नयी पीढ़ी आगे आ जाती है।

यही वह समय है, जब व्यक्ति को समाज सेवा के लिए अपनी रुचि का क्षेत्र चुन लेना चाहिए, जिसमें से राजनीति भी एक है। हां, यह ध्यान रहे कि उसे ७५ वर्ष का होने पर यहां भी नये लोगों के लिए स्थान खाली कर देना चाहिए।

यदि युवा पीढ़ी तीन सी (सिनेमा, क्रिकेट एवं कैरियर) से ऊपर उठकर देखें तो सैकड़ों मुद्दे उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ सकते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, कामचोरी, राजनीति में वंशवाद, महंगी शिक्षा और चिकित्सा, खाली होते गांव, घटता भूजल, आतंकवाद, माओवादी और नक्सली हिंसा, बंगलादेशियों की घुसपैठ, हाथ से निकलता कश्मीर, जनसंख्या के बदलते समीकरण, किसानों द्वारा आत्महत्या, गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई आदि तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इनसे कहीं अधिक स्थानीय मुद्दे होंगे, जिन्हें आंख और कान खुले रखने पर पहचान सकते हैं।

आवश्यकता यह है युवा चुनावी राजनीति की बजाय इस ओर सक्रिय हों। उनकी ऊर्जा, योग्यता, संवेदनशीलता और देशप्रेम की आहुति पाकर देश का राजनीतिक परिदृश्य निश्चित ही बदलेगा।

ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी का ऐतिहासिक कदम

जम्मू-कश्मीर के रामबन क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने एतिहासिक कदम उठाते हुए जिले के पिछड़े क्षेत्र सेना भत्ती में बिना किसी शुल्क के कोचिंग क्लास शुरू की गई। इस सेवा के दौरान आयोजित कक्षाओं में आठवी, नौंवी और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर एबीवीपी के प्रांत संगठन सचिव पवन शर्मा ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरदराज व आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों को शिक्षा के स्तर पर मजबूत बनाना है जिससे ये विद्यार्थी भी शहरी विद्यार्थियों की बराबरी कर पाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहरी विद्यार्थियों के पास हर तरह की सुविधायें उपलब्ध होती है और उनके माता-पिता भी शिक्षित होते है लेकिन इस पहाड़ी इलाके के विद्यार्थी सभी सुविधाओं से वंचित और पिछड़े हुए है।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह केतरवाल ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को ऐसी तालीम दी जाएगी जिससे वे अपने जीवन में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। इसके साथ-साथ केतरवाल ने सभी विद्यार्थियों से इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आग्रह किया है।

ज्ञातव्य है कि एबीवीपी के इस ऐतिहासिक कदम ने देहाती विद्यार्थियों की तरक्की व उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया है।

संप्रग सरकार के घोटालों का रिपोर्टकार्ड

अवनीश सिंह

एस-बैंड घोटाला

सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के नियंत्रण में काम करने वाली अंतरिक्ष संस्था इसरो ने एक निजी कम्पनी देवास के हाथ कौड़ियो के मोल लाइसेंस बेच कर देश को २ लाख करोड़ का चूना लगा दिया। इतनी रकम से छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य का हर व्यक्ति लखपति बन सकता था। इस घोटाले से न सिर्फ देश का आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गयी है। लाइसेंस लेने वाली कम्पनी में खुद इसरो के अधिकारी हिस्सेदार हैं। यह घोटाला सीधे प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है।

२ जी स्पेक्ट्रम घोटाला :- मोबाइल कंपनियों को नाम मात्र की कीमत पर लाइसेंस देकर एक लाख सत्तर हजार करोड़ का वारा-न्यारा कर दिया गया । इस धनराशि से देश भर में सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाये जा सकते थे। सीबीआई ने तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा को ही अपनी गिरफ्त में लिया है। लेकिन इतना बड़ा घोटाला क्या उन्होंने उच्च पदों पर बैठे लोगों की सहमति के बगैर कर डाला। नीरा राडिया के टेप से यह बात जाहिर हो गयी है कि राजा को मंत्री बनाने में दलालों एवं गैर संवैधानिक हस्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने यह रिपोर्ट दी है कि इस घोटाले के कारण देश का १.७७ लाख करोड़ रुपया लूट लिया गया।

कॉमनवेल्थ खेल घोटाला:- पिछले साल दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला फूटा। इसने सारी दुनिया के आगे देश का सिर शर्म से झुका दिया । पूरे आयोजन में ५८ हजार करोड़ की गड़बड़ी उजागर हुई है। आयोजन समिति के मुखिया सुरेश कलमाड़ी को इसका जिम्मेदार माना गया, पर अभी तक वे सिर्फ अपना पद गंवा कर सुरक्षित बचे हुए हैं।

आदर्श घोटाला:- मुंबई के पॉश इलाके में सेना की जमीन पर करगिल के शहीदों के लिए ६ मंजिला इमारत में फ्लैट बनाने की बात हुई। लेकिन नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से यह इमारत ३१ मंजिला बन गयी और शहीदों के लिए आरक्षित घरों की नेताओं और अफसरों ने बंदरबाट कर ली। सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल थे। फ्लैटों की बाजार में कीमत ८.५ करोड़ है। फ्लैट पाने वालों में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के साले, साली और सास भी शामिल हैं। घोटाले के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री को कुर्सी छोडनी पड़ी और उन पर मुकदमा भी चलाया जा रहा है।

खाद्यान्न घोटाला :- उत्तर प्रदेश में करीब ३५ हजार करोड़ रूपये का अनाज अफसरों ने मिलीभगत कर देश के दूसरे शहरों और विदेशों में बेच दिया। यह अनाज विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को दिया जाने वाला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घोटाले की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है। सात साल तक चली इस हेरा-फेरी को लेकर प्रदेश में करीब पांच हजार प्राथमिकी दर्ज हैं।

सड़ा खाद्यान्न घोटाला:- इस घोटाले में ५८ हजार करोड़ का नुकसान देश को हुआ है। आरोप है कि जानबूझ कर अनाज को सड़ाया गया ताकि शराब लॉबी को सस्ते दामों पर उसे बेचा जा सके। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखा ६७ हजार ५४२ टन अनाज सड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि इस अनाज को देश के ४० करोड़ गरीब लोगों के बीच बांट देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा शराब लॉबी को लाभ पहुंचाने की थी इसलिए उसने इसे मानने से इंकार कर दिया।

आवास ऋण घोटाला:- सीबीआई ने नवम्बर

२०१० में आवास ऋण घोटाले का भी पर्दाफाश किया। उसके मुताबिक यह पूरा घोटाला १००० करोड़ रूपये का है। इस सिलसिले में जीवन बीमा निगम आवास ऋण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्रन नायर के अलावा विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार किये गये ।

पामोलिन घोटाला :- घोटालों के आरोप से घिरे केरल कैडर के आईएएस अधिकारी पी जी थॉमस को आपत्ति के बावजूद मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया। केरल में वर्ष ९१.९२ में सिंगापुर से पामोलिन तेल आयात किया गया था । थॉमस पर यह आरोप है कि उन्होंने तेल की अधिक कीमत चुकाकर २.३२ करोड़ रूपये का नुकसान पहुंचाया था। २००३ में सतर्कता विभाग ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और आरोपियों की सूची में थॉमस का नाम शामिल किया। थॉमस को हटाने की मांग लम्बे समय से की जा रही थी लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए उसे बचाती रही। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थॉमस को पड़ छोड़ना पड़ा।

आईपीएल घोटाला:- कोच्चि टीम की नीलामी में गलत ढंग से संप्रग के मंत्री शशि थरूर की पत्नी की कम्पनी को १० प्रतिशत की हिस्सेदारी देकर करीब ७० करोड़ रूपये का घोटाला किया गया। इस मामले में जहां शशि थरूर को मंत्री पद गंवाना पड़ा वहीं इस घपले की सुई केन्द्रीय मंत्री शरद पवार एवम प्रफुल्ल पटेल की ओर भी घूमी। आरोप है कि इनके परिवार के सदस्यों का भी इसमें हिस्सा था।

महंगाई घोटाला:- इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला महंगाई है जिससे देश का हर आम नागरिक परेशान है। सरकार की नीतियों की वजह से बाजार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और बिचौलिये मालामाल हो रहे है। खाद्यान्न महंगा होता जा रहा है और सरकार मंहगाई की दर कम होने का दावा कर रही है।

काला धन:- घरेलू मोर्चे पर जहां देश की जनता बदहाल है वहीं वर्ग विशेष के लोगों की काली कमाई में अपार वृद्धि हुई है। दुनियां के २२ देशों में भारतीयों की १५ हजार करोड़ रूपये की काली कमाई जमा होने की जानकारी लग चुकी है । एक आकलन के अनुसार विदेशों में जमा धन भारत के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है । उन पैसों से देश के सभी हिस्सों की सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, मकान आदि की जरूरत पूरी की जा सकती है। यदि घोटाले की पूरी रकम का उचित उपयोग किया जाता तो शायद देश के हर नागरिक पर लदा विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता था। यह संदेह पैदा होने के पर्याप्त कारण हैं कि केंद्र सरकार जान-बूझकर काली कमाई करने वाले लोगों को बचा रही है।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आजादी के इतने बरसों के बाद भी देश में लंबे समय तक शासन का अनुभव रखने वाली कांग्रेस सरकार को अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए? भ्रष्टाचार ने सरकार की छवि को बट्टा लगाया है। भ्रष्टाचार के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी धूमिल हुई है। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि संप्रग सरकार घोटालों की प्रतीक बन गई है। आए दिन घोटाले की खबरें आ रही हैं। आजादी के बाद इतना कमजोर प्रधानमंत्री शायद ही किसी ने देखा हो, जिसका अपनी सरकार के काम-काज पर ही नियंत्रण नहीं है।

भ्रष्ट मंत्रियों को लुटेरों का गिरोह कहा जाय तो गलत नहीं होगा। देश को जितना विदेशी हमलावरों ने नहीं लूटा उतना इस सरकार में बैठे हुए लोग लूट रहे हैं। गोदामों में अनाज सड़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इस सरकार के मंत्री अफसर इतना कमा रहे हैं कि उसे स्विस बैंकों में जमा करवाना पड़ रहा है। सीमा पर जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे है उनके हिस्से के मकान तक इन लोगों ने हड़प डाले। आम भारतीय २० रूपये प्रतिदिन से भी कम में गुजारा कर रहा है और भ्रष्ट मंत्री घोटालों में अरबों-खरबों कमा रहे हैं। इस देश में भ्रष्ट लोग बेखौफ हैं, सुखी है। मेहनतकश उपेक्षित हैं, शोषित है और पीड़ित है।

आप इस सच्चाई को स्वीकारिये या धिक्कारिये. ..लेकिन नकार नहीं सकते। ईमानदारी के ताजमहल के बजाय झूठ का पिरामिड खड़ा करने में जितनी दिलचस्पी पीएम साहब ले रहे हैं उससे भारतीय राजनीति की तकदीर के सितारे जगमगाएंगे जरूर...लेकिन सिर्फ उजाले में।

भ्रष्टाचार कैंसर की तरह लाइलाज नहीं

एन. आर. नारायणमूर्ति

एक विकसित देश के रूप में भारत के उदय में मैं भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी बाधा समझता हूं। अब तो देश के सर्वोच्च और अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले संस्थान भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। सन् २००१ में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.पी. भरूचा ने आजिज आकर वक्तव्य दिया था कि न्यायालयों के २० प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्ट हो चुके हैं। अब जब हमारी न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की यह हालत है तो प्रशासन का क्या पूछना। प्रशासन में भ्रष्टाचार का फैलाव तो अत्यंत भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। इस सन्दर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का वक्तव्य सभी को याद होगा। उन्होंने कहा था कि गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक सौ करोड़ रुपए में मात्र १५ करोड़ रुपए ही मूल परियोजना में खर्च हो पाते हैं। शेष राशि बीच के सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े भ्रष्ट लोग खा जाते हैं।

लेकिन क्या भ्रष्टाचार केवल हमारी राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में ही व्याप्त है? मेरा अनुभव कहता है- नहीं। इनके बाहर जो हमारे व्यावसायिक समूह है, उनमें भी भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। हर्षद मेहता, केतन पारीख से जुड़े स्कैण्डल किसकी देन हैं? कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मानो भ्रष्टाचार हम भारतीयों के मन में एक स्वीकृत परिदृश्य बनकर गहरी पैठ कर चुका है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र इसकी पकड़ से बाहर हो।

भ्रष्टाचार केवल नैतिकता पर प्रश्न नहीं है बल्कि यह भारत जैसे गरीब किन्तु विकासशील देश की आर्थिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ में हमारे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी हैं। अधिकांश बड़ी-बड़ी परियोजनाएं इन्हीं लोगों के दिमाग की उपज होती हैं। जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के नाम पर बनने वाली परियोजनाओं में जबर्दस्त भ्रष्टाचार होता है। नकली दवाएं, विद्यालयों की जर्जर इमारतें, अयोग्य अध्यापक और स्तरहीन भोजन-व्यवस्था देकर आखिर किस तरह गरीबों का इस देश का भला किया जा सकता है? शायद इसीलिए प्रख्यात अर्थशास्त्री विमल जालान का यह कहना उपयुक्त है कि भ्रष्टाचार पहले से ही गैर-बराबरी वाले समाज में असमानता को बढ़ाता है।

भ्रष्टाचार का प्रभाव हमारे उद्यमों पर भी होता ही है। मध्यम श्रेणी के, लघु श्रेणी के उद्योग जहां इससे प्रभावित होते हैं, वहीं बड़े औद्योगिक समूह भ्रष्टाचार के द्वारा बाजार में अपना एकाधिकार और वर्चस्व कायम करने की होड़ करते हैं।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भ्रष्टाचार जहां हमारी प्रगति, उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है, वहीं इससे निवेश भी हतोत्साहित होता है। आर्थिक हानि के साथ लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास टूटता है। यदि हमारे देश में भ्रष्टाचार पर शुरू में ही लगाम लगाई जाती तो सम्भवतः ८०-९० के दशक में ही हमने ८ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर ली होती जो आज ६.१ प्रतिशत तक ही पहुंच सकी है।

आज लोग निराश हैं, सोचते हैं भ्रष्टाचार अब खत्म नहीं हो सकता, पर मैं उनमें नहीं हूं। मुझे भारत के उज्ज्वल भविष्य में पूरी आस्था है। भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो पहल उन लोगों से शुरू होनी चाहिए जो ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, जिन पर समाज ने, देश ने अपनी देखभाल का दायित्व सौंपा है। हमारे राजनेताओं, प्रशासकों और उद्यमियों को मिल-जुलकर इस मुसीबत से पार पाना है। सबसे पहले हमें प्रेरक, निःस्वार्थ और साहसी नेतृत्व चाहिए। सच्चाई, पारदर्शिता और दायित्व निर्वहन के द्वारा नेतृत्व सरकार और समाज में आत्मविश्वास पैदा करता है। दुर्भाग्यवश, आज यह स्थिति नहीं है। जरूरत इस बात की है

कि हम भ्रष्टाचारी को त्वरित ढंग से दण्ड देने की व्यवस्था करें। ऐसा वातावरण बने कि अभी भी ईमानदारी की कद्र है और ऐसा करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उदाहरण चाहिए। भ्रष्टाचार में आरोपित व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे किसी दायित्व पर तब तक नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि वह खुद को निर्दोष साबित न कर ले। त्वरित और कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। यदि ऊंचे पदों पर बैठे गलत तत्वों पर कार्रवाई हो तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे सकेंगे। पर आज तो वातावरण ऐसा है कि भ्रष्टाचार को वैश्विक परिदृश्य का अंग बताकर इसे हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्यता सिद्ध किया जा रहा है।

वस्तुतः हमारे राजनीतिक वर्ग और प्रशासनिक वर्ग के विरुद्ध जब भ्रष्टाचार के मामले में शिथिलता बरती जाती है, तो स्वभाविक ही समाज में संदेश चला जाता है कि ऊंचे बनने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने मे कोई हर्ज नहीं है।

"आज का वातावरण ऐसा है कि भ्रष्टाचार को वैश्विक परिदृश्य का अंग बताकर इसे हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्यता सिद्ध किया जा रहा है। वस्तुतः हमारे राजनीतिक वर्ग और प्रशासनिक वर्ग के विरुद्ध जब भ्रष्टाचार के मामले में शिथिलता बरती जाती है, तो स्वभाविक ही समाज में संदेश चला जाता है कि ऊंचे बनने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने मे कोई हर्ज नहीं है।"

हमारे प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में ईमानदार रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के मकड़जाल में उलझ जाते हैं। कैसे उलझते हैं, इससे संबंधित एक घटना मुझे याद है। सन् १९८० के दशक के मध्य में एक बार मैं दिल्ली आया हुआ था। एक शाम को होटल अशोक के यात्री निवास में डिनर पर मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र से हुई। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में उसकी गिनती एक ईमानदार और स्वच्छ चरित्र वाले आफिसर के रूप में थी। भोजन के समय मैंने उसे कुछ चिंतित पाया। बातचीत में उसने अपनी तकलीफ मुझे बताई।

उसने बताया कि जीवन में पहली बार आज उसने एक केस में रिश्वत ली है और तब से ही एक प्रकार की बेचैनी उसे परेशान किए है। मैंने कहा कि रिश्वत लेना तो गलत है, इसमें कोई संशय नहीं है। और तब उसने मुझे जो कहा, सुनकर मुझे धक्का लगा। उसने कहा कि मेरे विचारों का एक हिस्सा इस कार्य को उचित ठहराता है क्योंकि मैंने अपने मंत्री को रिश्वत लेते हुए देखा है। मैं अपने उस मित्र की मनःस्थिति समझ सकता था। मुझे वह कारण समझ में आ गया कि क्यों हमारे अच्छे-भले, उत्साही प्रशासनिक अधिकारी धीरे-धीरे इस मकड़जाल में उलझते जाते हैं। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि जिन्हें देश-समाज को दिशा देनी है, नेतृत्व देना है, वे इस प्रकार की उलझनों में नहीं फंसते। अनैतिकता को आखिर किस तर्क से नैतिकता का जामा पहनाया जा सकता है?

सिंगापुर में सन् ८० के दशक में एक घटना घटित हुई थी। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे एक मंत्री के विरुद्ध जांच में आरोप को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। उस मंत्री ने प्रधानमंत्री से स्वयं को निर्दोष बताते हुए हस्तक्षेप की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री ने उस मंत्री को स्पष्ट कहा कि आपका काम खत्म हो चुका है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और अब आगे चुनाव लड़ने का ख्वाब देखना भी छोड़ दीजिए। अपने नेता की बात सुनकर वह मंत्री घर चला गया।

अगले दिन समाचार पत्रों द्वारा पूरे सिंगापुर को खबर लगी कि उस मंत्री ने स्वयं ही सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो यह है वह संदेश, जिससे भ्रष्टाचार रुकता है, रुक सकता है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को कदापि कहीं से भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

हमारे कार्यों में पारदर्शिता झलकनी चाहिए। भ्रष्टाचार समाप्त करने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने चुनाव में खर्च होने वाले धन पर भी

नियंत्रण करें। इस बारे में हम जर्मनी का उदाहरण ले सकते है। वहां प्रत्येक प्रत्याशी पर खर्च होने वाले धन के बारे में जनता को जानकारी दी जाती है कि इतना पैसा प्रत्याशी ने कहां से जुटाया। हमें इसी के साथ ऐसा तंत्र भी विकसित करना पड़ेगा जो धन के अतिगमन पर न केवल नजर रखे वरन् जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई भी कर सके।

इस सन्दर्भ में चुनाव आयोग को और शक्तिसम्पन्न किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रत्याशी के अनाधिकृत और भ्रष्ट कार्यों को व्यापक रूप में प्रकाशित कर जनता को उससे अवगत कराना आवश्यक है। इस संदर्भ में त्रिलोचन शास्त्री और उनके सहयोगियों के चलते उठाए गए कदम का पूरे देश में अच्छा संदेश गया है।

प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ऐसे बहुत से कार्यों को उपायों को तलाशने की जरूरत है, जिनमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जैसे जब सरकार ने कम्प्यूटरों का आयात करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी, इलेक्ट्रॉनिक विभाग में फैला भ्रष्टाचार एक ही झटके में समाप्त हो गया। सरकार की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है कि वह जितनी नई योजनाएं बनाती है, प्रत्येक में सरकारी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए व्यवसायियों को भारी कशमकश का सामना करना पड़ता है। हमें प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की छोटी से छोटी संभावना का ध्यान रखकर उसे मिटाने के उपाय करने होंगे।

भ्रष्टाचार को दूर करने का एक बड़ा उपाय हमें ई-गवर्नेंस के रूप में मिल गया है। ई-गवर्नेंस ने निर्णय प्रक्रिया और निर्णय के क्रियान्वयन को भी अत्यंत आसान कर दिया है। हमें अपनी निर्णय-प्रक्रिया में अधिकाधिक पारदर्शिता रखनी होगी और इस कार्य में यदि हम साफ्टवेयर का इस्तेमाल सहज क्रियाशीलता के साथ प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय-प्रक्रिया में करते हैं तो मैं मानता हूं कि इससे सरकारी कार्यों और निर्णयों में पर्याप्त चुस्ती आएगी और भ्रष्टाचार की सम्भावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। ई-गवर्नेंस न केवल सेवाओं को सहज-सुलभ बनाता है बल्कि इससे यह पता लगाना भी आसान है कि कहां पर निर्णय या उसके क्रियान्वयन में देरी हो रही है।

हैदराबाद के ई-सेवा केन्द्रों ने साधारण जनता की कठिनाइयों को जिस तरह दूर किया है, वह इस सन्दर्भ में एक प्रेरक उदाहरण है। सरकार की उपयोगी सेवाओं, विविध प्रमाण पत्रों, सरकारी अभिलेखों, अनुपत्रों और तो और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के लिए देय शुल्क का भुगतान भी अब इसी माध्यम से होने लगा है।

आज हमें उत्तरदायी प्रशासन चाहिए। सरकारी कार्यों में गलती, लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश के अधिकांश लोकायुक्त असफल हो चुके हैं, क्योंकि एक तो उन्हें सरकार के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है, दूसरे उनके कार्मिकों की गुणवत्ता भी बेहतर नहीं है।

हमें अब एक अलग ज्यूरी खड़ी करनी होगी जो न्यायिक शक्तियों के साथ हमारी न्याय व्यवस्था के अंग के रूप में सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए त्वरित रूप में काम करे। इन्हें प्रशासकों और सरकारों के अन्तर्गत न रखकर केवल संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना होगा। साथ ही, ज्यूरी द्वारा निर्णीत मामलों में उच्च स्तर पर सुनवाई का अवसर भी निषिद्ध करना होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी इस संदर्भ में अपने हाथ में लिए गए मामलों मे जिस तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें सफल नहीं हुआ है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन कर उसमें तेज-तर्रार अफसरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किसी केस के बारे में प्राथमिक तथ्यों का अन्वेषण बारीकी से करके उस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

देश के औद्योगिक जगत, उद्यमी समूहों पर भी भ्रष्टाचार खत्म करने का दायित्व है। इन्फोसिस कम्पनी में हमने मूल्यों के क्षरण को रोकने के लिए इसी सन्दर्भ में एक कदम उठाया था। हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी ने जब हमारी मूल्य-परंपरा के विपरीत काम किया तो हमें निर्णय लेने में मात्र कुछ घण्टे लगे और उनका त्यागपत्र ले लिया गया। आज देश को दृढ़ निश्चयी और सुयोग्य नेतृत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहिए। ऐसे लोग हैं भी, बस जनता में विश्वास और कुछ करने का वातावरण बन जाए तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे।

ऐसे मिटाएँ भ्रष्टाचार

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत की राजनीति में आज भ्रष्टाचार जितना बड़ा मुद्दा बन गया है, पहले कभी नहीं बना। लेकिन अचंभा है कि किसी के पास उसका कोई ठोस इलाज़ दिखाई नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री माफी मांग लेते हैं और विपक्षी नेता उन्हें तुरंत माफ कर देती हैं। विपक्ष संयुक्त संसदीय कमेटी बिठाने का आग्रह करता है और सत्ता-पक्ष बिहारी की नायिका की तरह पहले नखरे करता है, संसद बंद हो जाती है और फिर वह खुद ढेर हो जाता है। दोनों के बीच अजीब-सी जुगलबंदी चल रही है। न्यायपालिका अगर चाबुक नहीं फटकारती तो सरकार और संसद क्या कर रही हैं, यह देश को पता ही नहीं चलता। दोनों आत्म-मुग्ध हैं कि उन्होंने संसदीय जांच कमेटी बिठा दी है।

यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिका का हस्तक्षेप और जांच कमेटियाँ देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करवा सकेंगी? उनकी अपनी सीमाएं हैं। अदालतें सजा तो तभी दे सकती हैं, जबकि भ्रष्ट आचरण सिद्ध हो। सिद्ध कौन करेगा? सरकारी वकील और सरकारी जांच एजेंसियां? वे क्यों करेंगी, कैसे करेंगी? सरकार अपना, अपने नेताओं का और अपने अफसरों का गला खुद क्यों काटेगी? बोफोर्स घोटाले का क्या हुआ? ६० करोड़ के घोटाले की जांच में ढाई सौ करोड़ खर्च हो गए। २५ साल बाद रो-धोकर सरकार ने सारे मामले पर ढक्कन दबा दिया। हसन अली न तो नेता है न अफसर । उसके विरूद्ध अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अदालतों की चीख-पुकार के बावजूद ७६ हजार करोड़ के हर्जाने में से अभी तक उससे एक पाई भी वसूल नहीं हुई। आखिर-क्यों? क्योंकि वह तो सिर्फ मुखौटा है। असली चेहरे तो कोई दूसरे ही हैं । ये चेहरे अपने मुखौटे को नुचने कैसे देंगे?

संसदीय कमेटियां और एजेंसियों की जांच तो वक्त काटने का बहाना है। जांच के नतीजे आने तक लोग सब कुछ भूल चुके होंगे। नेताओं को यह पता है। यदि वे सचमुच भ्रष्टाचार के विरुद्ध होते तो राष्ट्रकुल खेल और फोन-घोटाले की सारी राशि अब तक ब्याज समेत वसूल कर लेते। सारे अपराधियों और उनके सहायकों की चल-अचल संपत्ति जब्त कर लेते और ऐसा माहौल बना देते कि भावी अपराधियों की हड्डियों में कंपकंपी दौड़ जाती। इसमें शक नहीं कि इस तरह का प्रकंपकारी कदम कोई साहसिक नेता ही उठा सकता है लेकिन ऐसे नेतृत्व के अभाव में कम से कम हमारी सरकार और हमारी संसद कुछ कम आक्रामक कदम तो उठा ही सकती है। ये कदम दूरगामी और बुनियादी होंगे।

सबसे पहला काम तो यह होना चाहिए कि हमारी शासन व्यवस्था के चारों स्तंभों का वित्तीय ब्यौरा नियमित रूप से देश के सामने पेश किया जाए। ये चार स्तंभ हैं- विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका। ये चारों स्तंभ अत्यंत शक्तिशाली हैं। जहां शक्ति है, वहां भ्रष्टाचार है। विधानपालिका याने सिर्फ संसद नहीं, विधानसभाएं, विधान परिषदें, नगर-निगम, नगरपालिकाएं और पंचायतें भी। इन सबके सदस्यों की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं, हर साल सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यह भी काफी नहीं है। समस्त राजनीतिक दलों के समस्त पदाधिकारियों राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला कार्यकारिणी के सदस्यों तक का वार्षिक वित्तीय ब्यौरा जनता के सामने होना चाहिए। यह छोटा-सा कानूनी प्रावधान भारत की राजनीति की जबर्दस्त सफाई कर देगा। जो पैसा बनाने के लिए राजनीति की शरण लेते हैं, वे सब भाग खड़े होंगे।

जहां तक कार्यपालिका का प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेशों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का भी वार्षिक वित्तीय ब्यौरा देश के सामने होना चाहिए। इसी

किशोर चंद्रदेव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बनी थी लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यहां भी हुआ कि जांच ऐसी करो कि आंच किसी पर न आए। सारा मामला ही आया-गया हो गया, क्योंकि जांच करनेवाले और जांचे जानेवाले लोग एक ही होते है। ऐसी मिलीभगत से आज तक कभी कुछ ठोस नही निकला लेकिन एक अमेरिकी राजनयिक ने अपनी सरकार को इस कांड के बारे में जो गुप्त रपट भेजी थी, उसके छप जाने पर सरकार और संसद हिल गई है।

ऐसा इसलिए हो रहा है कि वह गुप्त रपट हमारी किसी भी जांच या फैसले से ज्यादा विश्वसनीय समझी जा रही है। किसी विदेशी कूटनीतिज्ञ को भारत के इस या उस दल और नेता से वैसा लगाव नहीं हो सकता, जैसा कि किसी भारतीय संस्था या व्यक्ति को हो सकता है। वह कोई झूठ बात क्यों लिखेगा? वह अपनी सरकार को गुमराह क्यों करेगा? वह वही लिखेगा जो उसे मालूम पड़ेगा या वह देखेगा। अमेरिकी राजनयिक ने जो रपट वाशिंगटन भेजी, उसकी तारीख ज़रा याद रखिए, १७ जुलाई २००८ थी। यानि २२ जुलाई को जो हुआ उसके पांच दिन पहले। पांच दिन बाद संसद में मतदान हुआ, एक करोड़ रू. की रिश्वत की गड्डियां उछाली गईं, सरकार बच गई। १६ सांसदों ने पाला बदला और १० ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या उस अमेरिकी राजनयिक को कोई सपना आया था? या वह कोई भविष्यवक्ता या ज्योतिषी है? उसने वही लिखा जो उसे सतीश शर्मा, उनके सहयोगी और अन्य सत्तारूढ़ स्त्रोतों से पता चला था।

उसकी रपट में जितने नेताओं के नाम आए हैं, सबने खंडन जारी कर दिया है। क्या उनके खंडन पर भारत की जनता विश्वास कर सकती है? एक नेता ने कहा कि मेरे सांसदों ने यदि दस-दस करोड़ खाए होते तो वे कांग्रेस के खिलाफ वोट क्यों देते? ये नेताजी इस वाक्य को पढ़ना शायद भूल गए कि "दस-दस करोड़ के बावजूद उनका कुछ भरोसा नहीं कि वे वोट किधर डालेंगे"। हो सकता है कि वे २०-२० करोड़ मांग रहे हो। हो सकता है कि वे पैसा और वोट दोनों ही डकार जाएं। यह मामला इतना नाजुक था कि पिटनेवाला आह भी नहीं भर सकता था। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वह तो यह मानने को ही तैयार नहीं है कि जुलाई २००८ में सांसदों को रिश्वत देने की कोई घटना भारत में घटी थी?

जरा देखें कि जब यह मामला संसद में गूंजा तो हमारे प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्रीजी ने संसद में कहा कि "मुझे सांसदों की खरीदी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है" उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह कहा कि "मैंने वोट खरीदने के लिए किसी को भी अधिकृत नहीं किया।" अब खुद को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उन्होंने दुबारा कहा कि "उस लेन-देन से मेरा कोई लेना-देना नहीं था।" इससे अधिक दो-टूक जवाब क्या हो सकता था? हो सकता है कि इस बयान का एक-एक शब्द सत्य हो। लेकिन पहली बात यह कि पूरा राष्ट्र आंखों देखी मक्खी कैसे निगल सकता है? जिस घटना को करोड़ों नागरिकों ने अपनी आंखों से टेलिविज़न पर देखा, उसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस मासूमियत पर कौन न मर जाए या खुदा? बेचारे असांज का मुंह हम कैसे बंद कर पाएंगे?

यदि रिश्वत के बंडलों को करोड़ों लोगों ने न देखा होता तो भी क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए यह कहना शोभा देता है कि "मुझे कुछ भी पता नहीं।" यदि यह सत्य है तो यही बयान प्रधानमंत्री की असलियत का पता भी बता रहा है। चाहे ए. राजा की कारगुजारियां हों, चाहे पी.जे. थामस की नियुक्ति हो, चाहे अंतरिक्ष-घोटाला हो और चाहे सांसदों का रिश्वत-कांड हो, सभी मामलों में प्रधानमंत्री की टेक एक ही है- मुझे कुछ भी पता नहीं। आप देश के सूचना-तंत्र, गुप्तचर-तंत्र और लोकतंत्र के सिरमौर हैं और आपको कुछ पता ही नहीं रहता तो फिर आपको इस पद पर बने रहने की मजबूरी क्या है? आपसे कौन जबर्दस्ती कर रहा है? आप अपनी और इस पद की साख निरंतर क्यों गिराए जा रहे हैं?

मान लें कि आप सचमुच पवित्रता के अवतार हैं और सारी तिकड़म कोई और ही कर रहा है तो यह भी लोकतंत्र का मजाक ही है। जुर्म कोई करे और हर्जाना कोई भरे। यदि सचमुच कोई रिश्वत-कांड हुआ ही नहीं तो किशोरचंद्र देव कमेटी

क्यों बिठाई गई थी? वैष-कमेटी ने रिश्वतों की जांच के लिए जो सुझाव दिए थे, उनको दरी के नीचे क्यों सरका दिया गया? अभी तक रिश्वत देनेवालों और लेनेवालों को पकड़कर अंदर क्यों नहीं किया गया? अब तो सरकार ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है कि रिश्वत देने को अपराध माना ही न जाए।

प्रधानमंत्री ने रिश्वत-कांड को अनहुआ सिद्ध करने के लिए अजब-सा तर्क दिया है। वे पूछते हैं कि यदि कांग्रेस रिश्वत की दोषी थी तो २००९ के चुनाव में उसकी सीटें क्यों बढ़ गईं और प्रतिपक्ष की सीटें क्यों घट गईं? क्या यही तर्क वे बोफोर्स-कांड पर लागू करेंगे और मानेंगे कि राजीव ने रिश्वत खाई थी? अपराधों के फैसले हम चुनावों से करने लगें तो देश की अदालतों पर ताले लग जाएंगे। इसी तरह वित्त मंत्री का यह तर्क भी बिल्कुल बोदा है कि पिछली लोकसभा के मामले पर इस लोकसभा में बहस नहीं हो सकती। दर्जनों नजीरें इस तर्क को गलत साबित करती हैं। उनके इस तर्क में भी कोई दम नहीं है कि विकीलीक्स के रहस्योद्घाटन पर वे इसलिए विचार नहीं कर सकते कि वे 'राजनयिक उन्मुक्ति' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना चाहते। जिस दस्तावेज को करोड़ों लोगों ने देख और पढ़ लिया हो, क्या अब भी वह गोपनीय रह गया है? इस सरकार की खूबी यह है कि जो बात सारी दुनिया को पता होती है, उसके बारे में वह कहती है कि 'मुझे कुछ भी पता नहीं।'

संविधान निर्माण के लिए नेपाल में छात्रों का अभियान

काठमांडू। मित्रराष्ट्र नेपाल में जनता के आंदोलन के बाद संविधान निर्माण के लिए तीन वर्ष पूर्व संविधान सभा का गठन किया गया था। निर्धारित दो वर्षों में संविधान सभा संविधान निर्मित कर पाने में असफल रही और समय सीमा को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया लेकिन नतीजा फिर भी पहले जैसा ही रहा। नेपाल में इस अस्थिरता के चलते राष्ट्रीय विद्यार्थी संगठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् ने संविधान निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी दबाव तथा जागरण र्‍याली अभियान का संचालन किया।

यह अभियान र्‍याली, धनगढ़ी, भैरहवा, बीरगंज, विराटनगर, पोखरा, जनकपुर, नारायणगढ, से आरंभ हुआ। अभियान के दौरान ''हामि सबै दाजुभाई'' और ''नेपाल आमाको जय'' जैसे नारे लगाए गए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभाप्रमुख और संविधान सभा के सभापति को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। ज्ञातव्य है कि नेपाल में संविधान निर्माण के लिए ये अभियान पहली बार प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद ने किया है।

भ्रष्टाचरण और कांग्रेस

सुरेन्द्र चतुर्वेदी

जरा याद कीजिये २००६ का आम चुनाव। कांग्रेस ने स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के गीत 'जय हो' को चुनावों हेतु अपने लिए ब्रांड गीत बनाया था, और उसी गीत को गांव-गांव बजाकर वह सत्ता के सिंहासन पर जा बैठी। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर सत्ता संभाल ली। सत्ता संभालने के दो साल बाद ही यूपीए सरकार की नीतियों के कारण आत्महत्या कर रहे किसानों पर बनी फिल्म 'पीपली लाइव' के जरिये एक और गीत सामने आया- 'सखी, सैंया तो बहुत ही कमात हैं, मंहगाई डायन खाए जात है।' ये दोनों गीत ही कांग्रेसी शासन की कथनी और करनी का अन्तर स्पष्ट कर देते हैं।

हाल ही में मुम्बई में सामने आए आवास घोटाले ने एक बार फिर साबित किया है कि कांग्रेस को सत्ता भ्रष्टाचार का नंगा खेल करने के लिए ही चाहिये। यह बार-बार याद रखे जाने की जरूरत है कि जैसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन नेतृत्व का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार आजाद भारत में सत्ता के सर्वाधिक दुरूपयोग और उसे भ्रष्ट करने के लिये जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गाँधी का नेतृत्व जिम्मेदार है।

दरअसल, कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल और सरकार के रूप में अपने अधिकार का इस कदर दुरूपयोग किया कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं भारत की संपूर्ण राजनीति भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गई। यह पूछा ही जाना चाहिये कि लोहिया और जयप्रकाश के शिष्य लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह ने राजनीति में भ्रष्टाचार करना कहां से सीखा? यह भी जानने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और मुसलमानों का पक्का वोट बैंक होने के बाद भी हर चुनाव में बसपा पर टिकट बेचने के आरोप क्यों लगते हैं? ऐसा कौन होगा जिसने राजनीति में शुचिता लाने के लिए कृतसंकल्प राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को एक लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए टेलीविजन पर नहीं देखा? और वामपंथियों ने तो भ्रष्ट आचरण की ऐसी आंधी चलाई जो केवल रूपये पैसे तक सीमित नहीं रही, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उसने कई बेगुनाहों को अपनी राजनीतिक बर्बरता का निशाना भी बनाया।

जब गंगा का उद्गम ही गंदा और अपवित्र हो तो वह पवित्रता कहां से प्रदान करेगी? आजादी के बाद कांग्रेस और विशेषकर नेहरू परिवार ने सत्ता का उपभोग किया है। यह ही वह समय था जब भारत के सम्मान और स्वाभिमान की नींव रखी जानी थी, इस दौर की ही सरकारों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे भारत के नागरिक को स्वच्छ, ईमानदार और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराते, जिसमें आम आदमी अपनी गरिमा को महसूस कर पाता। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा रास्ता चुनना ज्यादा बेहतर समझा, जिसमें उनके वंश और पीढ़ियों के राजनीतिक साम्राज्यशाही की रक्षा तो होती थी, परन्तु आम भारतीय पांच साल में एक बार वोट देने वाला ऐसा गरीब और बेबस मतदाता बन गया जो हर बार अपनी तकदीर संवारने के लिए वोट देता था, और उसे हर बार लुभावने नारों और विज्ञापनों के जरिये छल लिया जाता था।

दरअसल, नेहरू की कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की शुरूआत १९४८ में ही कर दी थी, जब कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ का जवाब देने के लिए सेना के लिए खरीदी जाने वाली जीपों में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कृष्णा मेनन की भूमिका सामने आई। इन्हीं कृष्णा मेनन की भ्रष्ट भूमिका को जानते बूझते हुए नेहरू सरकार ने ना केवल उनके खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया, अपितु कृष्णा मेनन के चुप रहने की कीमत पण्डित

जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें मंत्रीमंडल में शामिल कर के चुकाई।

भारत माता की सुरक्षा के लिए खरीदी गई बोफोर्स तोप से लेकर कारगिल में शहीद हुए सैनिक अधिकारियों के लिए मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसायटी द्वारा बनाए गए फ्लैटस घोटाले ने यह भी साबित कर दिया है कि कांग्रेस के लिए सैनिकों की कीमत एक चौकीदार से ज्यादा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक ने आज तक कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अपराधों के लिए देश से क्षमा नहीं मांगी है, अपितु वे इन मामलों में लीपा पोती करने की ही कोशिश कर रहे हैं।

आश्चर्य की बात तो यह है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को हिन्दुस्तान के अंदर दो हिंन्दुस्तान नजर आते हैं। एक गरीब हिन्दुस्तान और दूसरा अमीर हिन्दुस्तान। वे गरीब हिन्दुस्तानियों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए तरह-तरह के स्वांग रचते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन वे कभी आजाद भारत में हुए भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र प्रकाशित करने की बात नहीं कहते। वे यह भी नहीं कहते कि विदेशों में जमा काला धन भारत में लाने के लिए उनके पास क्या कार्ययोजना है। उनकी बातें तो बड़ी-बड़ी और साफ सुथरी हैं लेकिन क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि बोफोर्स तोप दलाल क्वात्रोची को किस राजनीतिक परिवार के संरक्षण के कारण भारत का कानून सजा नहीं दे पाया है? दरअसल, वे ऐसे राजकुमार की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए तरह-तरह के स्वांग रच रहा है। राहुल गांधी को चाहिये कि वे राजनीति से कुछ समय निकाल कर अपनी युवा टीम के साथ नॉक आउट फिल्म देखें, जिसमें विदेशों में जमा भारतीय मुद्रा को वापस लाने की फिल्मी कोशिश की गई है।

क्या कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक मामलों की जरा सी भी समझ रखता है, वो इस बात पर सहमत हो सकता है कि पिछले वर्ष संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में हुए भ्रष्टाचार में कांग्रेसी नेता शामिल नहीं थे? भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने खुद यह माना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की पूरे आयोजन की तैयारी में 'बड़ी भूमिका' थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नेहरू-गांधी परिवार के अति विश्वस्त लोगों के नाम ही भ्रष्टाचार करने में प्रमुख हैं। तेल के बदले अनाज घोटाले के मुख्य किरदार पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह आज कितने लोगों को याद हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी राजनीतिक परिदृष्य से गायब हैं।

कांग्रेस का यह तंत्र भ्रष्ट तरीके से अर्जित किये गए धन को वापस वसूलने की बजाय उस व्यक्ति को हटा देने में ज्यादा विश्वास रखता है, जिसका भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। कॉमनवेल्थ खेल हों या नरेगा कार्यक्रम कांग्रेस सत्ता किसी भी काम की शुचिता को बनाये रखने में विफल रही है।

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का अप्रैल अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसमायिक घटनाक्रमों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित कई महत्वपूर्ण आलेखों एवं खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव और विचार हमें नीचे दिये गये संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें-

"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005.
फोन : 011-43098248
ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाइट : www.abvp.org
ब्लॉग : chhatrashaktiabvp.blogspot.com

भारतीय नव-वर्ष की विशेषता

विनोद बंसल

भारत व्रत पर्व व त्यौहारों का देश है। यूं तो काल गणना का प्रत्येक पल कोई न कोई महत्व रखता है, किन्तु कुछ तिथियों का भारतीय काल गणना (कलैंडर) में विशेष महत्व है। भारतीय नव वर्ष (विक्रमी संवत्) का पहला दिन (यानि वर्ष प्रतिपदा) अपने आप में अनूठा है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। इस दिन पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तथा दिन-रात बराबर होते हैं। इसके बाद से ही रात्रि की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। काली अंधेरी रात के अन्धकार को चीर चन्द्रमा की चांदनी अपनी छटा बिखेरना शुरू कर देती है। वसंत ऋतु का राज होने के कारण प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। फाल्गुन के रंग और फूलों की सुगंध से तन-मन प्रफुल्लित और उत्साहित रहता है।

विक्रमी सम्वत्सर की वैज्ञानिकता :

भारत के पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किये जाने के कारण इसे विक्रमी संवत् के नाम से जाना जाता है। विक्रमी संवत् के बाद ही वर्ष को १२ माह का और सप्ताह को ७ दिन का माना गया। इसके महीनों का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति के आधार पर रखा गया। विक्रमी संवत का प्रारंभ अंग्रेजी कलैण्डर ईसवीं सन् से ५७ वर्ष पूर्व ही हो गया था।

चन्द्रमा के पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने को एक माह माना जाता है, जबकि यह २९ दिन का होता है। हर मास को दो भागों में बांटा जाता है- कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष। कृष्ण पक्ष में चांद घटता है और शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है। दोनों पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि ऐसे ही चलते हैं। कृष्णपक्ष के अन्तिम दिन (यानी अमावस्या को) चन्द्रमा बिल्कुल भी दिखाई नही देता है, जबकि शुक्ल पक्ष के अन्तिम दिन (यानी पूर्णिमा को) चांद अपने पूरे यौवन पर होता है।

अर्द्ध-रात्रि के स्थान पर सूर्योदय से दिवस परिवर्तन की व्यवस्था तथा सोमवार के स्थान पर रविवार को सप्ताह का प्रथम दिवस घोषित करने के साथ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष का आरम्भ करने का एक वैज्ञानिक आधार है।

वैसे भी इंग्लैण्ड के ग्रीनविच नामक स्थान से दिन परिवर्तन की व्यवस्था में अर्द्ध-रात्रि के १२ बजे को आधार इसलिए बनाया गया है क्योंकि उस समय भारत में भगवान भास्कर की अगवानी करने के लिए प्रातः ५-३० बज रहे होते हैं। वारों के नामकरण की विज्ञान सम्मत प्रक्रिया को देखें तो पता चलता है कि आकाश में ग्रहों की स्थिति सूर्य से प्रारम्भ होकर क्रमशः बुध, शुक्र, चन्द्र, मंगल, गुरु और शनि की है।

पृथ्वी के उपग्रह चन्द्रमा सहित इन्हीं अन्य छह ग्रहों पर सप्ताह के सात दिनों का नामकरण किया गया। तिथि घटे या बढ़े किंतु सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या को होगा और चन्द्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को होगा, इसमें अंतर नहीं आ सकता। तीसरे वर्ष एक मास बढ़ जाने पर भी ऋतुओं का प्रभाव उन्हीं महीनों में दिखाई देता है, जिनमें सामान्य वर्ष में दिखाई पड़ता है। जैसे वसन्त के फूल चैत्र-वैशाख में ही खिलते हैं और पतझड़ माघ-फाल्गुन में ही होती है। इस प्रकार इस कालगणना में नक्षत्रों, ऋतुओं, मासों व दिवसों आदि का निर्धारण पूरी तरह प्रकृति पर आधारित वैज्ञानिक रूप से किया गया है।

जो नापना हो इनकी उड़ानों को
तो ऊंचा कर लो आसमानों को

मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हुए प्रयासों ने
उन्हें आगे बढ़ने की मजबूत बुनियाद दी है।

अब वे बन रही हैं मालिक सुरक्षित, समर्थ और आत्मनिर्भर जीवन की।

- महिलाओं को 50% आरक्षण से पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में दो लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व कायम।
- चार लाख से अधिक बेटियाँ बनीं लाड़ली लक्ष्मी।
- हर वर्ष बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए मिलती है साइकिलें। अब तक दस लाख बालिकाओं को मिला लाभ।
- अड़तीस लाख बालिकाओं को मिली स्कूल यूनिफार्म।
- एक लाख से अधिक किशोरियों का कन्यादान।
- जननी सुरक्षा जैसी अनेक योजनाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य की संभाल।

मजबूत होती बुनियाद मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' मासिक पत्रिका
के सभी पाठकों को
भारतीय नव वर्ष की
हार्दिक शुभकामनायें।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

www.chhatrashaktiabvp.blogspot.com

शिक्षा क्षेत्र की अग्रणी पत्रिका

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राधिका तंवर को श्रद्धांजलि

भ्रष्टाचार के खिलाफ गोहाटी (असम) में कैंडल मार्च निकालते हुये अभाविप कार्यकर्ता

ABVP

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिष

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parisha